Reform in Criminal Justice System

*222. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision on the suggestions made by the Malimath Committee on reforming the Criminal Justice System and by the Law Commission in its 198th Report on ensuring the reliability of witnesses during deposition in criminal cases and also creating a Witness Protection Programme;

(b) if so, the details thereof and if no decision has been taken, by when it would be taken; and

(c) whether Government would also ensure that wide ranging discussions are held with the judiciary and other associations, like Bar Council of India in these issues?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The Malimath Committee on Reforms of Criminal Justice System has recommended that a law should be enacted for giving protection to the witnesses and their family members on the lines of laws in USA and other countries. The Report of the Committee has been referred to State Governments for their views as the Criminal Law and Criminal Procedure are on the Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution of India and are administered by State Governments.

The Law Commission in its 198th Report on "Witness Identity Protection and Witness Protection Programmes" has also recommended measures to provide protection to the witnesses. The contents of this Report are treated as confidential until the Report is laid in Parliament.

Though a final view on the feasibility of having a compreshensive scheme for protection of witnesses and their identity will be taken after considering the aforesaid report of the Law Commission in consultation with the State Governments, protection is being provided to the essential and material witnesses in very sensitive cases, as and when the Court so directs.

To ensure reliability of witness during deposition in court and also be contain the menace of witnesses turning hostile, the Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2006 has, *inter alia*, proposal to insert new section 164B and 344A in the Cdoe of Criminal Procedure, 1973 to provide that the statements of all persons which appear to be material and essential for proper investigation of the case relating to offences punishable with death or imprisonment for ten years or more shall be recorded on oath by Magistrate who will also satisfy himself that such person is making the statement voluntarily and not under any inducement, threat or promise and also to enhance the punishment for perjury after the summary trial.

(c) Yes, Sir.

श्री अमर सिंह: सभापति महोदय, अमेरिका एवं अन्य देशों की तरह गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मालिमथ कमेटी ने कानून बनाने की सिफारिश की थी। मैं इस संबंध में जानना चाहता हूं कि कौन से कारणों से हमारी सरकार ने ऐसा कानून नहीं बनाया जबकि दूसरे देशों में ऐसा कानून बनाया गया है?

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन् मालिमथ कमेटी में सुझाव दिया गया है कि विटनेस के प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाए जाएं। इस सुझाव को ध्यान में रखकर सरकार ने कानून में तबदीलियां भी की हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी बदलाव लाया गया है और जो दूसरे नए कानून बने हैं, उनमें भी इसकी तरतूत की गयी है। जो एक दूसरी रिपोर्ट लॉ कमीशन से आयी है, वह रिपोर्ट लॉ मिनिस्टरी के पास है और लॉ मिनिस्टरी जब तक उसे सदन के पटल पर नहीं रख देती है, तब तक उस रिपोर्ट की चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन उसमें भी यह प्रिंसिपल डिसकस किया गया है कि विटनेस को प्रोटेक्शन दी जाए और उसमें यह कहा गया है कि इस प्रकार की स्कीम बनानी चाहिए। दूसरे देशों का यहां पर जो संदर्भ दिया है, वह कानून के संबंध में उतना नहीं है जितना प्रोग्राम और स्कीम के संबंध में है। गवर्नमेंट को ये तत्व पूरी तरह से मानने हैं, उनको अमल में लाने के लिए गवर्नमेंट ने कानून में तबदीली की है और स्कीम बनाने का काम भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन यह स्कीमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अमल में लायी जाती है। और स्टेट गवर्नमेंट्स जब तक उसके संबंध में हां नहीं कहतीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हर जगह पर जाकर ये स्कीमें लागू करना मुश्किल होता है। इसीलिए आज की जो हालत है, वह इस प्रकार की है। कानून बनाने के लिए भी विचार करने पर यह लगता है कि हमें पूरे जीवन के लिए उनको सुरक्षा देनी है, उनके खाने-पीने का इंतज़ाम करना है, उनके नाम बदलने का इंतज़ाम करना है और कोर्ट में आने के बाद उनका जो एवीडेंस है, वह किस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाता है, इसके संबंध में चर्चा करनी

है। ये सारी चीज़े, जितना हम समझते हैं, उतनी आसान नहीं है। उसके लिए पैसा भी लगने वाला है, स्टेट गवर्नमेंट्स की सहायता की भी आवश्यकता है और हम लोगों की वैचारिक, मानसिक तैयारी भी इस संबंध में होनी जरूरी है।

श्री अमर सिंह: सर, आपके माध्यम से मैं दूसरा सप्लीमेंटरी पूछना चाहता हूं । क्या आदरणीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सीआरपीसी की धारा-164 में संशोधन करने के लिए कानून आयोग ने एक सुझाव दिया था कि तफतीश करने वाले अधिकारी गवाहों के वक्तव्यों को मजिस्ट्रेट के सामने रिकार्ड करेंगे। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पुलिस के दबाव में 90 प्रतिशत, कत्ल के मामले में गवाह अपने बयान से मुकर जाते हैं? इस संबंध में सरकार क्या कर रही है?

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: श्रीमन, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 164 के संबंध में हम जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का अमेंडमेंट यहां लाए थे, उसमें तरतूत की थी। लेकिन उसके स्टैंडिंग कमेटी में जाने के बाद स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि इस प्रकार की तरतूत नहीं होनी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी के कहने पर वह तरतूत वापस ली गयी। इसके बाद फिर चर्चा शुरू हो गयी कि जब विटनेस hostile हो जाते हैं, मुकर जाते हैं तो इस प्रकार की तरतूत होनी चाहिए। उनके कहने पर दूसरा जो हम एक और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अमेंडमेंट का बिल यहां पर ला रहे हैं, उसके अंदर कुछ पैमाने पर उस प्रकार की तरतूत करने की हमने कोशिश की है। विटनेस जब hostile होते हैं, तब उनको किस प्रकार से रोकना है, इसके ऊपर काफी चर्चा हुई है। एक बात यह बताई जा रही है कि ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग उनके स्टेटमेंट की होनी चाहिए, लिखित रूप से भी होनी चाहिए। उसके बाद अगर बड़े केसिज़ हैं जैसे मर्डर का केस है या रेप का केस है, डकैती का केस है या arson का केस है ऐसे केसिज़ के विटनेसिज़ का जो रिकॉर्ड होता है, मजिस्ट्रेट के सामने ले जाकर उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहिए। उसके ऊपर विटनेस के सिग्नेचर भी होने चाहिए। और मजिस्ट्रेट के भी सिग्नेचर होने चाहिए-वह कहा गया है। लेकिन इससे भी बढ़कर मैं एक आम बात जो सदन के सामने बड़ी नम्रता से रखना चाहता हूं, वह यह है कि जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो वहां पर खड़े हुए जो विटनेस होते हैं, वे गवाही देने के लिए सामने नहीं आते हैं। वे कहते हैं कि मर्डर हो गया है, मैं गवाही के लिए जाऊं और मेरी गवाही के आधार पर उसको सज़ा हो जाए, तो मेरे सारे जीवन तक वह दुश्मन बना रहेगा, इसलिए कह देते हैं कि हम थे नहीं, हमने देखा नहीं और इसमें कभी-कभी तो ऐसा हो जाता है कि जिन्होंने आधा देखा है, ऐसे विटनेसेज को सामने लाया जाता है और उसमें भी तकलीफ हो जाती है। यह जो मामला है, बड़ी गहराई में जाकर, जो जानकार लोग हैं, उनकी मदद से सुलझाना आवश्यक है, मगर कुछ कदम इसके लिए जरूर उठाए गए हैं, मेरी दृष्टि से वे पर्याप्त नहीं हैं, उससे भी ज्यादा करना जरूरी है।

DR. K. MALAISAMY: Sir, it is most welcome to protect the right witnesses at a right time. But we have been seeing in practice in criminal judicial system that there are stock witnesses, manufactured witnesses and made-up witnesses. I would like to ask whether there could be any move on your part to avoid these kinds of stock witnesses or professional witnesses or manufactured witnesses, which are prevalent in criminal judicial system.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: In fact, the question is hitting the nail on the head. It is a reality. As I have said in my previous reply, the real witnesses do not come forward, they are unwilling to give evidence and they think that if they depose in the court, the animosity between the accused and themselves is for their life time. So, they avoid and so these things have been happening. The question is what to do? How the system has to be modified, and we have applied our mind. The Committees have been appointed. The Commission has also looked into all those things and they have given their reports. One of the most important things which can be done in this respect is, not to rely very much on oral evidence, but to rely on circumstantial evidence. The third step which can be taken is to rely on technological evidence and fourth is forensic evidence, which is more important. The fifth step is to create a condition in the society in which full protection shall be given to the real witnesses and if there is any inducement or threat and if he is giving wrong evidence or false evidence under inducement or threat, he should be penalised also for giving wrong witness or withdrawing the evidence. If a witness has committed perjury previously, it was the Magistrate who had to file the complaint. We and you, hon. Members, have agreed to that amendment and we have introduced the amendment. Now the Magistrate can authorise anybody to file a complaint against such a witness and then the cases can be started. So, possible steps have been taken but, as I said in the reply to the previous question, fool proof solution is not becoming available and if there is any suggestion which can be given by the Members or the experts or jurists or lawyers or judges, they will be welcome and we will incorporate them.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Sir, you must say rightly or wrongly, but people are not very much satisfied with the administration of justice more because of delays and other hostile witnesses. However to involve the common man in the trials so that they understand the administration

of justice in a proper manner, do you propose to have live coverage of important trails in the country?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, we know what is happening to the live coverage of debate in the House. In my opinion, it has produced salutary effects and the suggestion given by the hon. Member is of a salutary kind. The proceedings in the court are public proceedings and they are open to anybody. If we are using the cameras to record the statement, there should be no difficulty in projecting what is happening in the court. outside the court on a larger scale. There should not be any difficulty. But how feasible and how workable it will be has to be discussed with judges, lawyers, clients and others.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, we have been seeing that in some cases, that too, very important cases, the media is conducting the trial outside the courts, which is rather trying to influence the minds of the Judges. So, may I know from the Minister whether the Government is contemplating any steps to prevent it?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, this is really a very, very important question, and it will be very very difficult for me to say 'Yes' or 'No' on this point. It is for exactly this reason that the *sub judice* matters are not allowed to be discussed on the floor of the House. Now, it is taken that if the matter, which is *sub judice*, is discussed on the floor of the House, it may influence the final judgement. It is for this reason that the *sub judice* matters are not allowed. But the media has the liberty to discuss and project the cases. The question is whether this liberty which is available to the media, and, rightly so, has to be used in a proper and responsible manner by the media. The answer certainly is 'yes'. But should there be a law to control them, or, should there be any other machinery to control them, probably this kind of proposition will not be accepted by us. And, so, we shall have to strike a balance here and the remedy really lies in not sensationalising the cases and not presenting the cases one way or the other, that is, supporting or opposing either the accused or the complainant; only then, this result can be achieved.

But, ultimately, this has to be left to the judgement, understanding, intelligence and ingenuity of our brothers and sisters in the media, and, also the people outside.